



2026:AHC:29859

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1964 सन् 2026

रामआशरे यादव

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: अनिल कुमार शुक्ला
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह अगस्त 1985 से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, लेकिन उसे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया गया है, जो कि सभाशंकर दुबे बनाम खण्ड वन अधिकारी, (2019) 12 एससीसी 297 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में 18000/- रुपये प्रति माह है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पहली बार में निर्णय की आवश्यकता है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार रिट याचिकाकर्ता के दावे पर आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"